an>

Title: Regarding non-implementation of recommendation of Muchkund Dubey and Kothari Commission on Uniform Education System.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मानव का विकास आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक चारों स्तर से होता है। वर्ष 1964 में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग बना और 24 जुलाई, 1968 को भारत की प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई, जिसमें मोरल एजुकेशन कंपल्सरी और कॉमन एजुकेशन को लाया गया। उसमें तकनीकी एजुकेशन को भी शामिल किया गया। वर्ष 1964 के कोठारी आयोग के बाद बिहार में एक मुचकुन्द दुबे कमेटी बनी। उस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी। उसमें कॉमन और कंपल्सरी एजुकेशन के बगैर गरीबों के विकास की कल्पना नहीं की गई।

मेरा आपके माध्यम से दो-तीन बिंदुओं पर आग्रह है कि एक तरफ हम कॉमन और कंपल्सरी एजुकेशन और मोरल एजुकेशन की बात करते हैं, समान ज्ञान की बात करते हैं, तकनीकी एजुकेशन की बात करते हैं और पूरे देश में हिंदी के साथ-साथ भाषा को स्कूल के ज्ञान में प्राथमिकता के आधार पर लाना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा, माध्यमिक शिक्षा में कोठारी आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि मिडिल क्लास के पहले 25 प्रतिशत बच्चों को कैसे तकनीकी एजुकेशन के माध्यम से लाया जाए, इस पर बल देने की बात कही गई। एक तो किसी भी कीमत पर एजुकेशन और स्वास्थ्य का व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। सरकार को कंपल्सरी और कॉमन एजुकेशन के लिए अपने स्तर पर एजुकेशन को रखना चाहिए, लेकिन आज भारत में जिस तरीके से व्यावसायीकरण हुआ है और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और माफियाओं का शिक्षा में आमूलचूल प्रवेश हुआ है, जिसके चलते भारत के गरीब, दलित, वंचित और कमजोर वर्ग इससे वंचित हैं।

मेरा आपके माध्यम से कहना है, इसको बहुत सीरियसली लिया जाए। मेरा आपसे सबमिशन है कि भारत सरकार किसी भी परिस्थिति में, यह जो प्राइवेट एजुकेशन का जाल बिछ रहा है और जो कोचिंग संस्थान हैं, उनके लिए कठोर कानून बने। सरकार अपने स्तर से गरीबों को कोचिंग दे। कंपल्सरी और कॉमन एजुकेशन, हाई मोरल एजुकेशन के साथ भाषाओं को प्राथमिकता के साथ तकनीकी एजुकेशन लाए। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है ताकि इस देश के गरीबों और वंचितों को लाभ मिल सके।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Shri Bhairon Prasad Mishra and

Shri Keshav Prasad Maurya are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajesh Ranjan.